E-Learning Study Material

By Prof (Dr) YADWENDRA SINGH

MAHARAJA COLLEGE, ARA

VKS UNIVERSITY, ARA, BIHAR

BA Part third Economics Hons

Paper Six.

Governments Policy of Small Scale Industries in Japan :-

4. लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं पड़ी था। ये इनके पूरक के रूप में काम करते थे।
5. महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बड़े पैमाने के उद्योगों के संपर्क में आने के कारण ये अपनी उत्पादन की शैली तथा यंत्रों को भी निरंतर आधुनिक बनाने का प्रयास करते रहे।
6. जापान में सस्ते श्रम और बिजली आपूर्ति से उत्पादन कार्य में बहुत अधिक मदद मिली।

गरीब किसान अपनी लड़कियों को खाली वक्त अथवा लघु उद्योगों में काम करने के लिए भेजते थे।

7. जापान की सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को हर तरह से प्रोत्साहित किया है और मदद किया है।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी नीति:-

1930 के पूर्व जापान सरकार की ~~मुख्य~~

नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात की वस्तुओं के गुण में सुधार था। सन् 1929-30 की मंदी के साथ सरकार ने लघु उद्योगों को सहायता देने के सम्बन्ध में अधिक सक्रिय नीति अपनायी। इस मंदी का रेशम उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था अतः सरकार ने इस उद्योग की सभी ~~शाखाओं~~ शाखाओं के लिए आर्थिक सहायता दी। मंदी काल में सरकार ने लघु पैमाने के निर्माता गिल्ड और निर्यात गिल्ड के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। इन्हें सरकार द्वारा निम्न ब्याज दर पर ऋण तथा छोटे-छोटे अनुदान दिये जाते थे जिससे ये सहकारिता के आधार पर क्रय-विक्रय कर सके। 1933 में जापानी मुद्रा येन (YEN) के अवमूल्यन के बाद विश्व में जब जापानी वस्तुओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई तो उसका लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में जापान सरकार ने इन्हें सरकारी संरक्षण में लघु उद्योगों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य को नियंत्रित करने का अधिकार दिया। 1948 में जापान सरकार ने एक लघु उद्योग मंडल की स्थापना की जो लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1948 में ही सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण की एक योजना कार्यान्वित की जो गाँवों उद्योग तथा कृषि में सहयोग पर आधारित है।